

सम्पादकीय

**क्या टिकट की मारामारी इसलिए
क्योंकि राजनीति ही सर्वाधिक ‘लाभ
का धंधा’ है?**

मध्यप्रदेश में विरोध के दिख रहे अलग-अलग तरीके

मध्यप्रदेश में जो सीन बन रहा है, वह इन सारे दृश्यों का नकारात्मक कोलाज है। बात अब विरोध के प्राचीन तरीकों जैसे कि नारेबाजी, धरना प्रदर्शन से मीलों आगे जाकर शीर्ष नेताओं के घरों के सामने आत्मदाह करने, पार्टी दफ्तरों पर हमले, नेताओं के कपड़े फाड़ने, हाथापाई, सामूहिक इस्तीफे और टिकट कटने के बाद मातमी अंदाज में जार-जार आंसू बहाने से लेकर इस परिस्थिति के लिए गलियां खाने की पावर ऑफ एटार्नी ट्रांसफर करने तक पहुंच गई है। अमूमन ये सब करने और करने वाले वही लोग होते हैं, जो टिकट कटने से पहले पार्टी के निष्ठावान और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कहलाते थे। आलम यह है कि कई जगह तो बड़े नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के हिंसक आक्रोश का शिकार होने से बचने जान बचाकर भागना पड़ रहा है। मानो सभी दलों में अनुशासनहीनता और अराजकता की एक अधोषित स्पर्द्धा चल रही हो, जिसमें हर असंतुष्ट अपने गिरोह के साथ दूसरे को पीछे छोड़ने की दबंगई में लगा है। ऐसा नहीं है कि आला नेताओं को कार्यकर्ताओं के इस तरह उग्र अथवा बागी होने का अंदाजा न हो। लेकिन पार्टीयां चुनाव का टिकट बांटती हैं तो टिकट देने और टिकट कटने के उसके अपने पैमाने होते हैं। कई बार तो ये पैमाने ही एक-दूसरे को काटते दिखाई देते हैं। मप्र में भाजपा और कांग्रेस ने जो सूचियां जारी की हैं, उसमें कोई निश्चित पैटर्न या फार्मूला नजर नहीं आता, सिवाय किसी कीमत पर सत्ता में लौटने या उसे कायम रखने की व्यग्रता के। इसमें नेताओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता, जुगाड़, डीलिंग, राजनीतिक शह और मात, तथाकथित सर्वे, निजी परसं- नापरसं-द, किसी भी हृद तक जाकर उपकृत करने की बेताबी और विवशता, जातिगत समीकरण, धन और बाहुबलीय क्षमता तथा अपने ही नैतिक प्रतिमानों का खुशी-खुशी विवरण भी इसमें शामिल है। तो ये पार्टियों में टिकट बांटने के लिए बैठकों पर बैठकें दृढ़ हैं। जोट-तोट

कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दरअसल ट्रांजिट बिंदु है। वहाँ हमारी छह-सात हजार कंपनियां हैं, जो भारत में निवेश कर रही हैं। सऊदी

सरक

दाना पाटियों में टिकट बाटने के लिए बठकों पर बठक हुई। जाड़- ताड़ जुगाड़ों के सत्र चले। गोपनीयता का आवरण ओढ़ा गया। हर दिन राजनीतिक हानि- लाभ का नया चौधड़िया रचने की कोशिशें हुईं। चेहरों के हिसाब से दर्पण सजाने के उपक्रम हुए। इतना कुछ हुआ कि भगवान् भी अगर इस टिकट वितरण का विश्लेषण करने वैठें तो चक्रवाजाएं यानी एक दिन पहले पार्टी में सामिल को भी टिकट मिले तो उन बुजुर्गों को भी टिकट से नवाजा गया जो खुद चार धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी में थे। कुछ को टिकट दिया भी उस क्षेत्र से, जहां उसे अपनी नेतागिरी का नायिल फोड़ा है। एक ऐसे नाराज माने जाने वाले विधायक को भी टिकट दिया गया, जिसने नातमीदी में टिकटों की घोषणा से पहले ही राजधानी में अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। कहीं भाई- भाई या सगे रिश्तेदारों को लड़ा दिया गया तो कहीं सालों से मेहनत करते कार्यकर्ता के हाथ में ऐन वक्त पर तुलसी पत्र पकड़ा दिया गया। कई उन मंत्रियों और विधायकों को फिर से टिकट मिल गया, जिन्होंने पांच साल में सिर्फ माल कमाया, अकड़ दिखाई और पब्लिक की गतियां खाईं। टिकट जुगाड़ों के लिए कहीं धमक काम आई, कहीं पैसा काम आया। कहीं सेवा का तड़का लगा तो कहीं चरणोदक्षि- ति दिखाई दी।

काम आया। अगर इस समूची प्रक्रिया में कोई ठग गया तो वह मतदाता। चुनाव पर क्या होगा इसका असर?

जाहिर है कि जब दो प्रमुख दलों में इन्हें बड़े पैमाने पर बगावत है तो उसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा ही। अपी करीब एक दर्जन टिकटवचित उमीदवार छोटे दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में उत्तरने का एलान कर चुके हैं। नाम वापसी तक यह संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि, नाराजों को बिठाने और चुप कराने के लिए दोनों? दलों में बड़े नेता साम-दाम-दंड-भेद सभी तरीके अपनाने में लगे हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता यह बहुबोधी

जानता है कि बड़े नेताओं द्वारा उससे किए वादे भी ज्यादातर चुनावी वादों की तरह खोखले अथवा आधे-अधूरे होते हैं। साथ में यह भी सच है कि बड़े दलों में अब वो ऋषि राजनेता नहीं रहे, जिनकी कार्यकर्ता के मन पर पकड़ थी और जो शीर्ष नेतृत्व और जर्मीनी कार्यकर्ता के बीच रेखमी धारण का काम करते थे। जो गरल को भी अमृत के भाव से पी सकते थे, पिला सकते थे। ऐसे दिगंत नेताओं का नैतिक प्रभाव खत्म होने के बाद आजकल कार्यकर्ताओं को मनाने का फार्मला मोटे तौर पर अगले चुनाव में टिकट के बाद, सत्ता में आने पर किसी पद की रेवड़ी, किसी कार्यकर्ता के घर जाकर चाय आदि पीने की दरियादिली या फिर बात-बेबात उसकी पीठ थपथपाने, मंच से तारीफ के दो शब्द कहकर भावनात्मक शोषण करने या फिर कैश डीलिंग के रूप में भी हो सकता है। ध्यान रहे कि राजनीति में 'ठगना' शब्द के अनेकार्थ हैं और वो परिस्थिति तथा पात्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। चुनाव के मंगलाचरण में अगर बड़े नेताओं का यह 'समझाइश कैम्पेन' खास सफल नहीं रहा और घोषित तौर पर बैठे प्रत्याशी ने अघोषित रूप से अंदर ही अंदर पार्टी पत्त्याशी को पलती लगा दिया तो नतीजे चौकाने वाले ही

ही अदर पाठा प्रत्याशा का पलाता लगा दिया ता नताज चाकान वाल हा सकते हैं।

धूमिल होती राजनीति की बुनियादी नैतिकता

यहां सबसे बड़ा सवाल तो राजनीति में बुनियादी नैतिकता का है? लोकतंत्र में चुनाव टिकट की आकांक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन उसे जीने-मरने का सवाल बना देना क्या संदेश देता है? क्या चुनाव का टिकट मिलना कोई कुबेर के खजाने की चाही है या उसका न मिलना घर के कर्ता पुरुष की असाध्यिक मौत है? टिकट न मिलने पर इतना शोक और रुदन क्यों? और मिल जाने पर आकाश स्पर्श का परमानन्द क्यों? दरअसल राजनीतिक व्यवस्था मूलतः लोकतंत्र को चलाने और इस तंत्र के असल मालिक लोक के जीवन को सुचारू और समृद्ध बनाने के लिए है, लोकतांत्रिक माफिया बनने के लिए तो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अमृत काल में यह कड़वा सच है कि राजनीति अब अधिकांश लोगों के लिए शुद्ध रूप से चौतरफा लाभ का धंधा है। इसीलिए वो इसे छोड़ना तो दूर इसे किसी सेठ की गद्दी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखना चाहते हैं ताकि पावर, पैसा और प्रतिष्ठा की दृष्टि से बदल दें।

परिचम एशिया का संकट और शांति बहाली की कोशिश

अहम हो सकती है भारत की भूमिका

अहम हो सकती है भारत की भूमिका



साथ संबंधों को बहाल करने के पक्ष में हैं, निश्चित ही कि दोनों देशों के बीच रिश्ट सामान्य होने में समय लगेगा जाहिर है कि इससे कॉरिडोरों के बनने में विलंब ही होगा जिसका नुकसान भारत के भी उठाना होगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों परियोजनाओं पर बात चल रही थी, वे भी संकट में पड़ सकती हैं। छठी बात इस्लाइन-हमास युद्ध पूर्व या की तरह भारत के मुस्लिम दाय को भी प्रभावित कर सकत खासकर गाजा में जो स्थितियाँ जिस तरह वहाँ के नागरिकों को बनाया जा रहा है, उन्हें कर भारत के मुस्लिम समुदाय भी आक्रोश भड़क सकता है। अतिक, भारत के लिए अच्छी बात है कि यहाँ के ज्यादातर लमान आतंकवाद में भरोसा नहीं तैरते हैं और यही उनकी भारतीयत इस्लाइल पर हमास के हमले के पूरी दुनिया दरअसल, बटी हुई बत्री है। कुछ आतंकी हमले में गए हजारों इस्लामियों के साथ नुभूति रखते हैं, तो कुछ वर्षों से इस सह रहे फलस्तीनियों के साथ दिखते हैं। भारत में भी यही अत है। लेकिन जरूरी यह है कि सहानुभूति को शांति और युद्ध दोनों देशों की तरफ मोड़ दिए जाएं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय

समुदाय का होना जरूरी है। भारत जैसे देशों को आगे आना चाहिए। मेरा मानना है कि इस्लाइल-हमास युद्ध में शांति बहाली के प्रयासों की अगुआई भारत को कही चाहिए। हम इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बना सकते हैं। पड़ोस के जो देश साथ देना चाहें, उनके साथ मिलकर युद्ध को रोकें की किसी योजना पर काम कर सकते हैं। हम नई दिल्ली के जी-20 सम्मेलन में भी देख चुके हैं कि आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है। पश्चिम एशियाई देश भी चाहते हैं कि भारत आगे आए। आज उसकी साख है। भारत जब कहता है, तो दुनिया सुनती है, क्योंकि वह सिद्धांतों की बात करता है। भारत की स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए और फांस फेंच लोगों के लिए है, उसी तरह फलस्तीन फलस्तीनियों के लिए है। 1948 में जब पहली बार बोट हुआ, तब भारत ने फलस्तीन को बांटने के प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। 1950 में भारत ने अधिकारिक तौर पर इस्लाइल राज्य को मान्यता दी, लेकिन अधिकारिक राजनीतिक संबंध 1992 में जाकर स्थापित किए। दोनों देशों को लेकर फिलहाल भारत का पक्ष दो-राज्य समाधान और शांतिपूर्ण ढंग से दोनों देशों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ डी-हाईफेनेशन की नीति की ओर बढ़ गया है। जब इस्लाइल पर हमला हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस्लाइल के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई। फिर विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि भारत दो-राज्य सिद्धांत का हिमायती है। फिर जब गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 500 लोग मरे गए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की थी। भारत दरअसल, बिलकुल संतुलित रखता रखते हुए चाहता है कि वहां शांति की स्थापना हो और कोई रास्ता निकले। दोहा, कतर, तुर्कीये और मिस्र जैसे देश शांति बहाली के लिए वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस्लाइल जमीनी लड़ाई पर उतरता है, और जिस तरह से हिजबुल्ला, लेबनान की तरफ से दबाव बनाए हुए हैं, उससे तो युद्ध का लंबा खिचना तय लगता है। रूस-यूक्रेन और अब इस्लाइल-हमास के बीच युद्धों ने वैश्विक व्यवस्था को बदलने का काम किया है और इनके नीति वी बताएँगे कि दुनिया किस तरफ जाएगी। मुमकिन है कि शीतयुद्ध 2.0 जैसी स्थिति हो, जिसमें रूस, चीन व कुछ देश एक तरफ और अमेरिका व यूरोपीय देश दूसरी तरफ हों। तीसरे पक्ष की भूमिका अगर कोई निभा सकता है, तो वह भारत है, जो रणनीतिक स्वायत्ता की नीति अपनाते हुए उन तमाम देशों को जोड़ सकता है, जो किसी भी गुट में शामिल न होना चाहें।

सरकार के नौ साल और विकास के मार्ग पर हरियाणा



जहां पहले परिणामों में हेरफेर किया गया था। कॉमन पात्रता परीक्षा की शुरुआत की, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए न तो बार-बार आवेदन करना पड़े और न हर बार फीस देने की नौबत आए। रुप सी के लिए अब तक 11 लाख युवा परीक्षा में बैठ चुके हैं। रुप डी की परीक्षा 22 अक्टूबर को संपन्न हुई, जिसमें 8.51 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। बेरोजगारों के लिए भर्ते की नतीजतन राज्य की वर्ष 2023 के अनुसार, 6.5 सैमित हो गई है, जो वर्ष पंजाब से कम है। वर्ष 2023 के प्रदेश में नया निवेश गया था। ऐसे में, नए अनुकूल माहौल भ्रष्टाचार के छिपों को राजस्व की हानि भी दिखने लगा है, जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण का भी असर है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत के पार है, तो प्रति व्यक्ति आय 2014 के 1.35 लाख रुपये से बढ़कर जून, 2023 में 2.96 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। मुझे किसानों की हरदम चिंता रहती थी। इसमें भी टेक्नोलॉजी का मेरा अनुभव काम आया। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' योजना से न केवल किसान को उपज बेचने की सहूलियत हो गई है, बल्कि उसका पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने लगा है। अब तक 85 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। हम हरियाणा को एक आदर्श, विकसित राज्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमने जिन योजनाओं की शुरुआत की है, उन्हें अन्य राज्य भी अपनाने लगे हैं। आगामी एक नवंबर को हरियाणा 57 वर्ष का हो जाएगा। प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम नए हरियाणा की विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आजादी के अमृत काल के समापन पर वर्ष 2047 में हम हरियाणा को देश के एक अग्रणी विकसित राज्य के रूप

यद्यु. अर्थात्यवस्था और मानवता की चनौतियों के बीच हैरान करती है सैन्य खर्च में बढ़ोतरी

विमान पर साढ़े सात करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। जब यह उड़ रहा होगा, तब हर घंटे करीब 42 हजार डॉलर धूआं हो रहे होंगे। ज्यादा कुशल माने जाने वाले एफ-15 विमान की हर उड़ान में प्रति घंटे करीब 29 हजार डॉलर का खर्च आता है। आयरन डोम इस्टाइल की सुरक्षा प्रणाली में कवच की तरह है। ऐसा अनुमान है कि पूरे इस्टाइल में करीब दस आयरन डोम बैटरी हैं। हर बैटरी में 60 से 80 मिसाइलें हैं और हर मिसाइल की कीमत तकरीबन 40 हजार डॉलर है। बीते गविवार को अमेरिकी सरकार ने अरबों डॉलर की अत्यधिक थाड प्रणाली भेजने की घोषणा की। बोइंग ने इस्टाइल को 1800 जीपीएस आधारित बम किटों की शीघ्र डिलीवरी की घोषणा की, जिनमें से प्रत्येक किट की कीमत करीब 24 हजार डॉलर है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्वी भूमध्य सागर में 13 अरब डॉलर के विमानवाहक पोत स्ट्राइक रूप की तैनाती की घोषणा की। यह रूप 75 लड्डूकू जेट, रडार और मिसाइल लॉन्चर से सुसज्जित है। एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत 15 लाख डॉलर और एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब 40 लाख डॉलर है। युद्ध के हथियार वौरह बनाने वाली कंपनियों के लिए युद्ध मुनाफे का समय होता है। यह शेयरों की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव से भी स्पष्ट होता है। सात अक्टूबर के हमलों के बाद इससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछल देखा गया। इस क्षेत्र की शीर्ष दस कंपनियों का वर्तमान बाजार पूँजीकरण 653 अरब डॉलर है। बिजनेस रिसर्च कंपनी द्वारा जारी 2023 की वैश्विक रक्षा बाजार रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक रक्षा बाजार का आकार बढ़कर 718 अरब डॉलर का होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि युद्धों की इस भारी-भरकम लागत का पैसा कहां से आता है? यह दरअसल, बहुत राजनीति पर यूक्रेन के रुपरेखा, फरवरी, 2022 ने 40.4 अरब मुकाब्ला सहायता की संयुक्त जरूरत है। इस हफ्ते इस्टाइल और अमेरिका के लिए कांग्रेस उपलब्ध कराया गया है। इस पर सवाल उठा समझौतों को ६ अक्टूबर के अमेरिकी और मानना है कि और हौथिस धन व तकनीक लेकिन सवाल है कि इतने प्रति इन गुटों के अमेरिकी से और सौ से अमेरिका के जैक सुलिवन

राजनीति पर निर्भर करता है। अब यूक्रेन के युद्ध को ही लें। 24 फरवरी, 2022 से अमेरिकी सरकार ने 40.4 अरब डॉलर से ज्यादा की सुरक्षा सहायता की प्रतिबद्धता जारी है, जो माल्टा और यमन जैसे देशों की संयुक्त जीडीपी के लगभग बगबर है। इस हफ्ते भी व्हाइट हाउस ने इस्ताइल और यूक्रेन का समर्थन करने के लिए काग्रेस से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। पर सवाल उठता है कि आरंकवादी समूहों को धन कैसे मिल पाता है? अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि ईरान हमास, हिजबुल्ला और हौथिस जैसे आतंकी गुटों को धन व तकनीकी मुहैया कराता है। लेकिन सवाल फिर भी बना हुआ है कि इन्हें प्रतिबंधों के बावजूद धन इन गुटों के पास पहुंचता कैसे है? अमेरिकी सांसद एलिजाबे वैरन और सौ से ज्यादा दूसरे सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान को एक पत्र लिखकर उन्हें चाहते हैं कि वे अपने दोस्तों को अपने दोस्तों के लिए सैन्य खर्च बढ़ाया जाना वाकई दिलचस्प है। विश्व बैंक के एक अनुसार के मुताबिक, दुनिया की 9.3 फीसदी आबादी यानी करीब 70 करोड़ लोग बेहद गरीबी में हैं, जो रोज 2.15 डॉलर से भी कम कमा पाते हैं। मिसाल के लिए, गाजा में रहने वाले हर दस में सात लोग वैश्विक मदद पर निर्भर हैं। मध्य पूर्व का युद्ध कितना लंबा खिचेगा, यह तो नहीं कह सकते। पर यह जरूर है कि अफगानिस्तान और ईराक के युद्धों में अमेरिका ने 80 खरब डॉलर खर्च किए हैं। वाद्यन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के अध्ययन के मुताबिक, अमेरिका में 9/11 हमले के बाद से लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौतों और अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद वहाँ के लोगों में शायद ही अपेक्षित होता है।

